

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून दिनांक-26 दिसम्बर, 2007

विषय: नगर पालिका परिषद, किच्छा के अन्तर्गत अवरस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष-2005-06 में स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 262/V-शवि-06-189(सा0)/2005, दिनांक 06.2.2006 का सद्वर्तन ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से नगर पालिका परिषद, किच्छा जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वारह कार्यों हेतु रु0-356.50 लाख की लागत के आगमन के विपरीत रु0-354.28 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या 801/V-शवि-06-66(सा0)/03 टी0सी0 दिनांक 29 मार्च, 2006 के द्वारा रु0 233.94 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। नगर पालिका द्वारा अपने पत्रांक 166/अवरस्थापना निधि/2007 दिनांक 8-10-2007 के माध्यम से प्रस्तुत किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र ने उक्त शासनादेश के द्वारा स्वीकृत कार्यों के क्रमांक-12 के कार्य 'मेटाडोर स्टेण्ड निर्माण स्थल' में विवाद होना अवगत कराये जाने के कारण उक्त कार्य की स्वीकृति को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 6-2-2006 के क्रमांक-12 के उक्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि रु0 10.65 लाख (रु0 दस लाख पैंसठ हजार मात्र) को उक्त शासनादेश दिनांक 6-2-2006 के माध्यम से स्वीकृत अन्य कार्यों हेतु स्वीकृति अवशेष धनराशि रु0-109.69 लाख (एक करोड़ नौ लाख उन्हत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष स्वीकृत करती हुए रु0 10.65 लाख उक्त योजना की धनराशि के लिए स्वीकृत धनराशि को अन्य चालू कार्यों पर तथा शेष 109.69 लाख के विपरीत वर्तमान वित्तीय वर्ष के आग-व्ययक से रु. 80.00 लाख (रुपये अस्सी लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रशिक्षणों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि रु. 80.00 लाख (रुपये अस्सी लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर संबंधित नगर पालिका को बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से उपलब्ध करावी जायेगी, जो शासनादेश की शर्तों पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगी।
2. शासनादेश संख्या 262/V-शवि-06-189(सा0)/2005, दिनांक 06.2.2006 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगमनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अप्रतिर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में उपयोग करते हुए कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
6. कार्यों की सम्यक्बद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः

7. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV/219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अवकाश आगमन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-03-2008 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- 2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों का सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-06- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अनुदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के असा0सं0- 528/XXVII(2)/2007, दिनांक- 18 दिसम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव।

सं0-उ४ 7 (1)/IV-श0वि0-07, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, राजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी०आई० में इसे शामिल करें।
9. अध्यक्ष/अधेशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, किच्छा।
10. राजट राजकोषीय नियोजन एवं ससाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फुल।

आज्ञा से,
(गोपाल कृष्ण द्विवेदी)
अपर सचिव।